खास-खबरें

एपल के पहले मुड़ने वाले फोन की बुकिंग आज से

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रौद्योगिकी कंपनी एपल के पहले मुड़ने वाले स्मार्टफोन आईफोन डुओ की भारत में बुकिंग शुक्रवार शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। ग्राहक इसे कंपनी के आधिकारिक ऑनलाइन भंडार, खुदरा दुकानों और अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से बुक कर सकेंगे। इसकी आपूर्ति और दुकानों में बिक्री 23 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।

आईफोन डुओ कंपनी का अब तक का सबसे महंगा आईफोन बताया जा रहा है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 2.99 लाख रुपये है, जबकि शीर्ष मॉडल की कीमत 4.50 लाख रुपये तक जाती है। चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को सात हजार रुपये तक की नकद वापसी मिल सकती है। कुछ कार्ड पर 12 महीने तक बिना अतिरिक्त ब्याज के किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। फोन में बाहर की ओर 5.4 इंच की स्क्रीन दी गई है, जबकि खोलने पर इसकी मुख्य स्क्रीन 7.6 इंच की हो जाती है। कंपनी के अनुसार, यह अब तक के किसी भी आईफोन में दी गई सबसे बड़ी स्क्रीन है। मुड़ने वाली बनावट के कारण उपयोगकर्ता इसे बंद करके सामान्य फोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और खोलने पर बड़ी स्क्रीन का लाभ उठा सकते हैं। इस उपकरण में ए20 प्रो चिपसेट दिया गया है। इसमें भौतिक सिम कार्ड लगाने की सुविधा नहीं होगी। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक सिम के माध्यम से काम करेगा। ऐसे में ग्राहकों को खरीदारी से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका दूरसंचार सेवा प्रदाता इलेक्ट्रॉनिक सिम की सुविधा उपलब्ध कराता है।

फेडरल बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 45.10 फीसदी उछलकर 1386 करोड़ रुपये

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक लिमिटेड ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे का ऐलान कर दिया है। बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने मुनाफा (शुद्ध लाभ) में 45.10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिससे यह उछलकर 1,386.09 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। फेडरल बैंक के मुनाफे में सालाना आधार पर मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 45.10 फीसदी बढ़कर 1,386 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 955 करोड़ रुपये रहा था। इसी तरह बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) सालाना आधार पर 26.4 फीसदी बढ़कर 3,153.4 करोड़ रुपये रही है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 2,495.2 करोड़ रुपये थी। बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 26 आधार अंक बढ़कर 3.32 फीसदी हो गया है, जबकि जमा की लागत 39 आधार अंक घटकर 5.18 फीसदी हो गई।

बैंक ने कहा कि फेडरल बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता पिछले एक दशक के सबसे अच्छे स्तर पर रही है। इस दौरान बैंक का ग्रॉस सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सुधरकर 1.32 फीसदी और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 0.17 फीसदी पर आ गए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे निचले स्तर हैं।

गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करने पर चीनी मिल के विरोध में किसान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने शुक्रवार को गन्ना मूल्य वृद्धि सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर गन्ना समिति बिजनौर में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद अपर जिलाधिकारी अंशिका दीक्षित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान बिलाई शुगर मिल के खिलाफ चल रहे 'भुगतान नहीं तो गन्ना नहीं' आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने मिल को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के भुगतान में देरी का आरोप लगाते हुए करीब 10 हजार किसानों के शपथ पत्र प्रशासन को सौंपे। संगठन का दावा है कि कुल 31 हजार 753 गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों में से 20 हजार किसानों ने भुगतान न होने की स्थिति में अपना गन्ना दूसरी चीनी मिल को आवंटित कराने का अनुरोध किया है।संगठन ने आरोप लगाया कि बिलाई शुगर मिल के शीरे से संबंधित लगभग आठ करोड़ 15 लाख रुपये तथा खोई से संबंधित करीब 10 करोड़ रुपये की राशि डायवर्ट की गई है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी और मिल प्रबंधन की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिला आबकारी अधिकारी को अपने बीच बैठाकर इस मामले में जवाब भी मांगा। संगठन ने कहा कि किसानों के गन्ना भुगतान के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग की जांच कराई जानी चाहिए। जिला अध्यक्ष नितिन कुमार सिरोही ने कहा कि 31 हजार 753 किसानों में से 20 हजार किसानों के शपथ पत्र भरवाना किसानों के असंतोष को दर्शाता है।

टेस्ला ने दिखाई उड़ने वाली कार, कलाबाजी के बाद सुरक्षित उतरी रोडस्टर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने शुक्रवार को अपनी दूसरी पीढ़ी की रोडस्टर कार का प्रदर्शन किया। इस दौरान कार एक बड़े घुमावदार ढांचे पर चढ़ी, उल्टी हुई और हवा में उछलने के बाद कलाबाजी करते हुए जमीन पर सुरक्षित उतर गई। कंपनी के अनुसार, इस कार में रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली प्रणोदन तकनीक का उपयोग किया गया है।

प्रदर्शन के दौरान कार की विशेष क्षमताओं को दिखाया गया। दावा किया गया कि यह केवल 0.81 सेकंड में 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। हालांकि, यह अभी प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया प्रारूप है। इसकी

वास्तविक क्षमता और उत्पादन के समय मिलने वाली सुविधाओं की पुष्टि होना बाकी है।

मस्क ने बताया कि कार में अत्यधिक दबाव वाली हवा के भंडारण की व्यवस्था है। इसमें हवा में नियंत्रण के लिए विशेष प्रणोदक और पीछे की ओर मुख्य प्रणोदक लगाए गए हैं। इनकी मदद से कार को

रॉकेट तकनीक से लैस कार 0.81 सेकंड में 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने का दावा, 2028 में उत्पादन की तैयारी

अतिरिक्त धक्का और हवा में नियंत्रित गति देने की योजना है। मस्क ने इसे टेस्ला और स्पेसएक्स के अभियंताओं के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया।

कार का उत्पादन 2028 में शुरू होने की संभावना है। इसकी बुकिंग के लिए 50 हजार डॉलर, यानी लगभग 48 लाख रुपये जमा करने होंगे। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यह राशि वापस की जा सकती है।

रफ्तार के मामले में कंपनी ने कई दावे किए हैं। रोडस्टर की अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बताई गई है। मस्क ने भविष्य में लगभग 617 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल करने का लक्ष्य भी बताया है। हालांकि, ये लक्ष्य हैं और इन्हें उत्पादन वाले वाहन में हासिल करना अभी प्रमाणित नहीं हुआ है।

टेस्ला ने दूसरी पीढ़ी की रोडस्टर को पहली बार नवंबर 2017 में प्रदर्शित किया था। शुरुआत में इसका उत्पादन 2020 तक शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन डिजाइन और निर्माण संबंधी चुनौतियों के कारण इसमें देरी हुई। कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक रोडस्टर 2008 में बाजार में आई थी।

प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते, भारत में स्टारलिंक का स्वागत:रिलायंस

- एलन मस्क के आरोपों के बीच कंपनी का बयान
- भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए तीन कंपनियों को मिला अनुमति पत्र

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत को लेकर जारी विवाद के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वह प्रतिस्पर्धा से नहीं डरती और स्टारलिंक का स्वागत करती है। कंपनी ने सामाजिक माध्यम पर जारी संदेश में कहा कि वास्तविक प्रतिस्पर्धा से ही पता चलता है कि कौन बेहतर सेवा दे रहा है।

यह बयान एलन मस्क के उन आरोपों के बाद आया है, जिनमें उन्होंने भारत में स्टारलिंक की शुरुआत में देरी के लिए भारतीय दूरसंचार कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया था। मस्क ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी पर भी निशाना साधा था।

भारत में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार, रिलायंस जियो सैटकॉम, भारती एयरटेल के सहयोग वाली यूटेलसेट वनवेब और एलन मस्क की

स्टारलिंक को अनुमति पत्र दिए जा चुके हैं। हालांकि, इन कंपनियों को सुरक्षा संबंधी मंजूरी और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उपग्रह आवृत्तियों के उपयोग के लिए शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है।

स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसका उपयोग उन दूरदराज के क्षेत्रों में किया जा सकता है, जहां मोबाइल नेटवर्क और पारंपरिक इंटरनेट की पहुंच सीमित है।

हालांकि, भारत में इसकी व्यावसायिक शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं है। सेवाएं शुरू होने के बाद कीमतें, उपलब्धता और अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगी कि भारतीय उपभोक्ता इस सेवा को कितना अपनाते हैं।

सभी कंपनियां भारतीय कानूनों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें

उपग्रह इंटरनेट सेवाओं के लिए रेडियो आवृत्तियों की आवश्यकता होती है। इनके आवंटन को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच मतभेद रहे हैं। रिलायंस जियो नीलामी के माध्यम से आवृत्तियां देने की पक्षधर रही, जबकि कुछ अन्य कंपनियों ने सीधे आवंटन का समर्थन किया। सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत सीधे आवंटन का रास्ता चुना है। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी कंपनियां भारतीय कानूनों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें। इसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत निगरानी और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने जैसी शर्तें शामिल हैं।

सुरक्षित संचार और विश्वसनीय नौवहन के लिए नई पहल

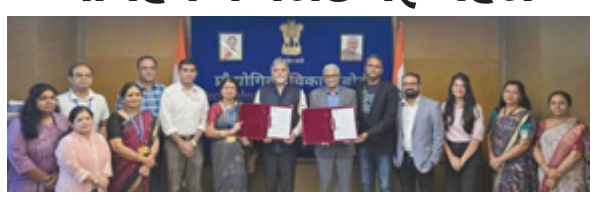

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत की क्वांटम प्रौद्योगिकी और सुरक्षित संचार क्षमता को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बेंगलुरु स्थित क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का समझौता किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत यह सहायता अनुसंधान, विकास एवं नवाचार निधि से दी जाएगी।

कुल 300 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य भारत के लिए क्वांटम-सुरक्षित संचार और संवेदन तंत्र का स्वदेशी आधार विकसित करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रारंभिक विकास स्तर से आगे बढ़ाकर ऐसे स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जहां उनका व्यावहारिक उपयोग और तैनाती संभव हो सके। वित्तीय सहायता परिवर्तनीय ऋण के

- 300 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत क्वांटम प्रौद्योगिकियों को उन्नत स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य

माध्यम से प्रदान की जाएगी। परियोजना के चार प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला उपकरणों की पहचान और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, दूसरा स्थान निर्धारण तथा नौवहन प्रणालियों की विश्वसनीयता बनाए रखना, तीसरा संचार नेटवर्क को सुरक्षित करना और चौथा सटीक समय निर्धारण तथा समकालिकरण की व्यवस्था विकसित करना है।

उपकरणों की सुरक्षा के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित की जाएंगी, जिनसे उनकी विशिष्ट पहचान सुनिश्चित हो सके और उनकी नकल या पहचान के साथ छेड़छाड़ की आशंका कम की जा सके।

घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल

- सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी का असर
- विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी रही। बीएसई का सेंसेक्स 413 अंक चढ़कर 74,729 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 148 अंक की बढ़त के साथ 23,146 पर पहुंच गया। सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली।

एशियाई बाजारों में भी कारोबार के दौरान तेजी रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 114 अंक यानी 2.05 प्रतिशत बढ़कर 5,668 पर पहुंच गया। जापान का निक्केई 898 अंक यानी 1.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 65,324 पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 124 अंक यानी 0.52 प्रतिशत चढ़कर 24,187 पर पहुंच गया। इससे पहले अमेरिकी बाजारों में भी तेजी दर्ज की गई थी। डाउ जोन्स 556 अंक यानी 1.08 प्रतिशत बढ़कर 52,178 पर पहुंच गया। नैस्डैक में 20 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 26,713 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 सूचकांक 25 अंक यानी 0.33 प्रतिशत चढ़कर 7,744 पर पहुंच गया। हालांकि, घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रही। पिछले सात कारोबारी दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 10,157 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। पिछले 30 दिनों में उनकी शुद्ध बिकवाली 89,516 करोड़ रुपये रही। इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पिछले सात दिनों में 11,474 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की।

पूर्वोत्तर में प्याज की आपूर्ति बढ़ाएगी कांदा एक्सप्रेस, पहली बार अगरतला पहुँचेगी खेप

- त्रिपुरा के लिए भेजा गया 440 मीट्रिक टन प्याज
- त्यौहारी मौसम में किफायती दरों पर उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: त्यौहारी मौसम से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को किफायती बनाए रखने के लिए सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था का विस्तार किया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, पहली बार कांदा एक्सप्रेस के माध्यम से त्रिपुरा के अगरतला के लिए प्याज भेजा गया है। लगभग 440 मीट्रिक टन प्याज की यह खेप 18 अक्टूबर 2026 तक पहुंचने की उम्मीद है।

इस पहल से त्रिपुरा के आठ में से सात जिलों धलाई, दक्षिण त्रिपुरा, खोवाई, उनाकोटी, पश्चिम त्रिपुरा, गोमती और सेपाहिजाला में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार, अब तक दो विशेष रेल खेपों और 44 ट्रकों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2,800 मीट्रिक टन से अधिक बफर प्याज पहुंचाया जा चुका है। असम, त्रिपुरा और नागालैंड के विभिन्न स्थानों पर इसकी आपूर्ति की गई है। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक प्याज पहुंचाना और स्थानीय बाजारों में उपलब्धता बेहतर करना है।

नई खरीफ फसल की आवक बढ़ने से प्याज की मंडी कीमतों में भी गिरावट आई है। अखिल भारतीय औसत मंडी भाव सितंबर में लगभग 3,600 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर से घटकर अक्टूबर में करीब 3,300 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है। पिछले दो सप्ताह में 211 शहरों में खुदरा प्याज की कीमतों में एक से 13 रुपये प्रति किलोग्राम तक की कमी दर्ज की गई है। असम के लगभग 12 केंद्रों में भी प्रति किलोग्राम एक से आठ रुपये तक की गिरावट आई है।

असम में प्याज का औसत खुदरा मूल्य अब 54.30 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 53.07 रुपये है। इससे दोनों के बीच का अंतर घटकर 1.23 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है। सरकार बाजार में प्याज की आवक, कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर रख रही है। मूल्य स्थिरीकरण कोष से जरूरत के अनुसार प्याज जारी किया जाएगा, ताकि पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे और कीमतों में अनुचित उतार-चढ़ाव को रोका जा सके।

12 राज्यों के 77 संस्थान कर रहे स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी' अभियान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुंबई में खादी महोत्सव-2026 का शुभारंभ किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने 15 अक्टूबर को विले पार्ले स्थित आयोग के केंद्रीय कार्यालय में महोत्सव का उद्घाटन किया। यह आयोजन 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा।

महोत्सव में 12 राज्यों की 77 इकाइयां अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रही हैं। इनमें 36 खादी संस्थान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़ी 33 इकाइयां और ग्रामोद्योग की आठ अन्य इकाइयां

शामिल हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान की इकाइयां इसमें भाग ले रही हैं।

प्रदर्शनी में खादी के कपड़े, रेशमी वस्त्र, तैयार परिधान, हर्बल उत्पाद, खाद्य सामग्री, साबुन, अगरबत्ती, मसाले, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी के खिलौने, थैले, कृत्रिम आभूषण और हस्तशिल्प उपलब्ध हैं। ग्राहकों को खादी उत्पादों पर 20 प्रतिशत और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है।

मनोज गोयल ने कहा कि महात्मा गांधी ने खादी को आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया था। अब युवाओं की रचनात्मकता, तकनीकी समझ और उद्यमशीलता के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने खादी को आधुनिक फैशन, आकर्षक डिजाइन और बदलती जीवनशैली से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक माध्यमों, ऑनलाइन व्यापार और डिजिटल विपणन के जरिए स्थानीय उत्पादों को देश के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है।

पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पांच गुना बढ़ा, डीजल पर 7.50 रुपये की कटौती

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बदलाव किया है। पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पांच गुना बढ़ाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में 7.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से घोषित नई दरें 16 अक्टूबर से लागू हो गई हैं और अगले दो सप्ताह तक प्रभावी रहेंगी।

सरकार का उद्देश्य देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर तेल कंपनियों को विदेश में ईंधन बेचने से अधिक लाभ मिल सकता है। ऐसी स्थिति में घरेलू बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका रहती है। निर्यात शुल्क में बदलाव के माध्यम से सरकार घरेलू जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। इस फैसले का असर विदेश भेजे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा।

स्पेशल खबर अंतर्देशीय जलमार्गों से माल ढुलाई 21.8 करोड़ मीट्रिक टन पहुंची

जलमार्गों से माल परिवहन में तेजी से बढ़ोतरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुगम और किफायती बनाने के लिए जलमार्गों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। जल सर्वेक्षण, नौवहन संकेतक, नदी आधारित प्रकाशस्तंभ और डिजिटल मानचित्रों की सहायता से जहाजों की आवाजाही को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 20,187 किलोमीटर है। ये 23 राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हैं। इनमें 32 जलमार्गों पर वर्तमान में परिचालन हो रहा है। अंतर्देशीय जलमार्गों से माल ढुलाई वर्ष 2014-15 में 2.9 करोड़ मीट्रिक

टन थी, जो 2025-26 में बढ़कर 21.8 करोड़ मीट्रिक टन हो गई। जल परिवहन सड़क की तुलना में लगभग एक-तिहाई और रेल की तुलना में आधी लागत पर माल ढुलाई का विकल्प उपलब्ध कराता है। इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नदियों की गहराई, तलछट, रेत के उथले क्षेत्रों और बहाव में होने वाले बदलावों का नियमित सर्वेक्षण करता है। इन सर्वेक्षणों से नौवहन के लिए उपलब्ध सबसे गहरे मार्ग की पहचान होती है। सितंबर 2026 तक 22 राष्ट्रीय जलमार्गों पर नियमित सर्वेक्षण किए जा रहे थे। इनके आधार पर गाद हटाने, मार्गों के रखरखाव और सुरक्षित आवागमन की योजना बनाई जाती है। नौवहन को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के पहले चार नदी आधारित प्रकाशस्तंभों की घोषणा की गई। पांडु, बोगीबील, सिलघाट और बिश्वनाथ घाट में विकसित की जा रही इस परियोजना पर 74 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये प्रकाशस्तंभ सौर ऊर्जा से संचालित होंगे और इनमें मौसम संबंधी जानकारी देने वाले संवेदक भी लगाए जाएंगे। इनसे रात में जहाजों की आवाजाही को सहायता मिलेगी।

असम में धुबरी से सदिया तक फैला राष्ट्रीय जलमार्ग-2 कुल 891 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग पर माल ढुलाई 2024-25 के नौ लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 12.9 लाख मीट्रिक टन हो गई। बढ़ते यातायात के कारण इस मार्ग पर सुरक्षित नौवहन सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ी है। डिजिटल व्यवस्था के तहत सितंबर 2026 तक 18 परिचालित और ज्वारीय जलमार्गों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नौवहन मानचित्र तैयार किए गए हैं। इन्हें संबंधित डिजिटल मंचों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इनसे नाविकों को जल की गहराई, मार्ग और नौवहन संबंधी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।

तमिलनाडु से बुल्गारिया पहुँचा जैविक ताड़ के गुड़ का पाउडर

नईदुनिया ब्यूरो, चेन्नई: भारत के पारंपरिक कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने तमिलनाडु से बुल्गारिया के लिए जैविक ताड़ के गुड़ के पाउडर की पहली खेप रवाना करने में सहायता प्रदान की। 15 अक्टूबर को तमिलनाडु के इरोड जिले के गोबिचेट्टीपलयम से 1.755 मीट्रिक टन उत्पाद बुल्गारिया के वर्ना के लिए भेजा गया।

यह खेप राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम और यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप प्रमाणित है। इसका निर्माण इरोड की वेलबीइंग फूड्स ने चेन्नई की चेट्टी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है। उत्पाद को चेन्नई बंदरगाह से समुद्री मार्ग के जरिए भेजा जाएगा। बुल्गारिया की सो लाइफ लिमिटेड इसकी आयातक और वितरक कंपनी है।

इस पहल का उद्देश्य तमिलनाडु के पारंपरिक ताड़ उत्पादों के लिए नए बाजार विकसित करना और जैविक खेती करने वाले किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के अंतर्गत 137 एकड़ भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। निर्यात से किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में लगभग 15 से 22 प्रतिशत अधिक मूल्य मिलने की उम्मीद है, जबकि निर्माताओं को करीब 17 प्रतिशत अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है।

ताड़ के फूलों के रस से तैयार होने वाला गुड़ का पाउडर भारत का पारंपरिक मीठा उत्पाद है। इसमें परिष्कृत चीनी के विकल्प के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने की संभावनाएं हैं। ताड़ के पेड़ से जुड़े उत्पाद तमिलनाडु की कृषि और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने खेप को रवाना किया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव सस्वती बोस, वरिष्ठ अधिकारी, निर्यातक कंपनियों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष उपस्थित रहे।